by M/s Pepsi Foods Ltd. during the last 2 years is as udner:—

Year	Total Foreign Exchange earned (FOB Value) (Rs. in lakhs
1992-93	3585.98
1993-94	4040.64

(b) The original terms of approval were applicable during 1992-93 and the same were amended in July 1993. Interpretation of the original terms and conditions of approval is yet to be finalised. As per the latest approval, M/s Pepsi Foods Ltd. has projected to export products worth Rs. 400 crores over a period of 10 years.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के अवसर

3871. **श्री आस मोहम्मद:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 तक कितने रोजगार के अवसर पैदा किए गए?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और उनमें सृजित नौकरियों के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। बहरहाल, उद्योग के संगठित क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित अथवा रहित 174 यूनिटों ने वाणिज्य रूप से उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इनमें 29,000 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के मार्फत मार्च, 1974 तक प्राप्त अथवा मंजूर किए गए विभिन्न निवेश प्रस्तावों से पता चलता है कि उनसे लगभग 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इन निवेश प्रस्तावों को लागू करने में दो से तीन वर्ष का समय लगेगा।;

दूध से संबंधित प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार

3872. **चौधरी हरमोहन सिंह: क्या खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि दूध से संबंधित प्रसंस्करण सुविधाओं के स्तर में सुधार करने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) से (ग) दूध से संबंधित प्रसंस्करण सुविधाओं के स्तर में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत में कतिपय दूध प्रसंस्करण संयंत्रों के स्तर की तुलना विश्व में किसी भी उन्नत देश से की जा सकती है।

Meat Processing Plants

3873. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what is the present number and location of meat processing plants in the joint sector and what are the reasons for Government's participating in these projects;

(b) the number of meat processing plants which process beef and pork together, with quantity of each product; how much of this quantity is exported and how much is conserved internally;

(c) what is the total quantity of meat exported and value thereof in 1991, 1992 and 1993 and what is the quantity of beef and pork out of the above together with the value thereof; and

(d) what is the amount of assistance provided by Government for the development of meat processing in 1991-92, 1992-93 and provision made in the budget for 1994-95 together with the names of the recipients?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF THE FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) At present, there are no joint sector (between public sector & private entreprise) meat processing plants in operation. However, some joint sector buffalo/sheep/goat, and poultry/egg processing plants are being set up in pubjab Uttar Pradesh, Haryana and Andhra Pradesh. These are being set up for developing this industry in scientific lines with a view to produce meat and poultry/egg products hygienically,

mainly for exports as well as for domestic consumption.

(b) There are five meat processing units in Goa on small scale which process beef and pork together in small quantities. Such products are not exported as export of beef is banned.

(c) The total quantity of meat exported and the value thereof in the year 1991-92, 1992-93 and 1993-94 are as follows:

Year	Quantity in M.Ts.	Amount (Rs. in lakhs)
1991-92	89,081.00	22,169.00
1992-93	89,003.40	25,462.95
1993-94	110,713.00	38,700.00

The calendarwise information is not maintained. Out of the above quantity, 6.4 MT valued at Rs. 0.95 lakhs is pork. The export of beef is banned.

(d) The assistance provided under different Plant schemes of the Ministry for developing meat and poultry sectors is as follows:

1991-92	—	Rs. 323.39 lakhs
1992-93	—	Rs. 291.35 lakhs
1993-94	—	Rs. 352.56 lakhs
1994-95 (Provisional)	—	Rs. 604.60 lakhs

The names of the recipients of the assistance are given below:

1. UP Pashydhan Udyog Nigam Ltd., Aligarh.
2. A.P. Meat & Poultry Development Corpn., Hyderabad.
3. MAF Co., Bombay.
4. Assam Livestock & Poultry Corpn., Guwahati.
5. MP Livestock & Kukkut Vikas Nigam Bhopal.
6. Manipur State Poultry Farmers Cooperative Federation, Imphal.
7. Manipur State Piggery Farmers Cooperative Federation, Imphal.
8. Indian Veterinary Research Institute, Izzatnagar, UP.
9. Indian Institute of Packaging, Bombay.
10. Central Food Technology Research Institute, Mysore.
11. Toni Multipurpose Cooperative Society, Dimapur Thru' Govt. of Nagaland.
12. Mizoram Food & Allied Industries Corpn. Aizwal.
13. Karnataka Meat & Poultry Marketing Corpn., Bangalore.
14. Punjab Agro Industries Corpn., Chandigarh.
15. AP Industrial Development Corporation, Hyderabad.
16. Sukar Palak Samiti, Bhopal.
17. Poultry Cooperative Society, Aurangabad, Maharashtra.
18. Sikkim Livestock Products Corpn., Gangtok.
19. Al Majbooh Cooperative Society Rampur, U.P.
20. Bihar Veterinary College, Patna.
21. Bombay Veterinary College, Bombay.

कम लागत वाली प्रौद्योगिकी प्राप्त करना

3874. श्री ईश दत्त यादव:
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भण्डारण प्रसंस्करण और विपणन के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी को जुटाने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) से (ग) सरकार देश में भण्डारण प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि के लिए कम लागत/लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहन/सहायता दे रही है। सरकार ने उद्यमियों द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने को भी उदारीकृत कर दिया है और ऐसे विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिए स्वत: मंजूरी की अनुमति है जिनमें कुल जानकारी, डिज़ाइन और ड्राइंग शुल्क आदि एक करोड़ रु से अधिक